

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1657 जिसका उत्तर
गुरुवार, 11 फरवरी, 2021/22 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है
उप-बंदरगाहों का विकास

†1657. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री निशीथ प्रामाणिक:

डॉ. जयंत कुमार राय:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री. भोला सिंह:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार सभी प्रमुख बंदगाहों द्वारा उप-बंदरगाहों के विकास सहित भविष्य की कार्य-योजना की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार शहरी परिवहन और एसएआरओडी-पोर्ट्स के कार्यान्वयन (सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स-पोर्ट्स) के नए विस्ता की खोज कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो मोबाइल हार्बर क्रेन की एक खेप की आपूर्ति की है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या अन्य कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

- (क) और (ख): एक्जिम व्यापार में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए तथा महापत्तनों में भीड़ से बचने के लिए उन्हें सुझाव दिया गया है कि वे अपने आस-पास के क्षेत्र में सैटेलाइट/सिस्टर पत्तनों का विकास करने के लिए संभावनाओं की खोज करें।
- (ग) और (घ): जहां तक शहरी परिवहन के नए विस्तार का संबंध है, सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए शहरी परिवहन के लिए नए जलमार्गों की पहचान की है। हाल ही में, गुजरात में हाजिरा - घोघा के बीच रो- पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। जहां तक एसएआरओडी - पोर्टस (सोसाइटी फॉर ऑफर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स-पोर्ट्स) का संबंध है, इसका गठन पहले से ही हो चुका है और यह सोसाइटी दिनांक 30/01/2020 को पंजीकृत की गई।
- (ङ) से (छ): जी हां, भारत सरकार ने ईरान के चाबहार पत्तन, ईरान को 140 मी. टन क्षमता के दो मोबाइल हार्बर क्रेनों (एमएचसी) की एक खेप की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। भारत सरकार यूएस 85 डॉलर की कुल लागत पर चाबहार पत्तन को लैस करने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि उसे पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक बनाया जा सके।
